भारत सरकार   लोक सभा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय   अतारांकित प्रश्न सं.2545
वाणिज्य विभाग

दिनांक 16 दिसम्बर,2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव

2545. श्री पुट्टा महेश कुमार:

श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत दो वर्षों के दौरान भारतीय उद्योगों, व्यवसायों, किसानों और स्थानीय समुद्री उत्पाद निर्यातकों पर अमेरिकी टैरिफ/भारी टैरिफ के प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन/सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो विगत दो वर्षों के दौरान भारतीय उद्योगों, व्यवसायों और किसानों को अमेरिकी टैरिफ के कारण हुए कुल अनुमानित नुकसान का माहवार और राज्यवार विशेषकर आंध्र प्रदेश में ब्यौरा क्या है;

(ग) टैरिफ लागू होने के बाद से सरकार द्वारा प्रभावित भारतीय उद्योगों, व्यवसायों, किसानों और स्थानीय समुद्री उत्पाद निर्यातकों को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने टैरिफ से प्रभावित देश के व्यवसायों को नुकसान की भरपाई करने और नए संभावित बाजार विकसित करने में मदद करने के लिए उक्त कदमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): भारत सरकार, भारत के निर्यात पर निगरानी रखती है और उन्हें बढ़ावा देने के लिए कदम उठाती है।

(i) पिछले वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 की समान अवधि की तुलना में वर्तमान वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर की अवधि में भारत के निर्यात कार्य-निष्पादन का विवरण नीचे दिया गया है:

(मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

	अप्रैल- नवंबर 2023	**अप्रैल- नवंबर 2024**	**अप्रैल- नवंबर 2025**
निर्यात	**278.80**	**284.60**	**292.07**

स्रोत: डीजीसीआईएस

(ii) पिछले वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 की समान अवधि की तुलना में वर्तमान वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर की अवधि में भारत के समुद्री उत्पाद के निर्यात कार्य-निष्पादन का विवरण निम्नवत है:

(मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

	अप्रैल- नवंबर 2023	**अप्रैल- नवंबर 2024**	**अप्रैल- नवंबर 2025**
निर्यात	**5.22**	**4.95**	**5.75**

स्रोत: डीजीसीआईएस

(iii) विश्व को आंध्र प्रदेश राज्य से पण्यवस्तु निर्यात संबंधी निर्यात कार्य-निष्पादन नीचे दिया गया है:

	विश्व को आंध्र प्रदेश से निर्यात	**विश्व को आंध्र प्रदेश से निर्यात**
(मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	**2023-24**	**2024-25**
आंध्र प्रदेश से निर्यात	19759.86	20782.81

स्रोत: डीजीसीआईएस

(ग) और (घ): सरकार अमेरिकी टैरिफ उपायों के उभरते प्रभाव का आकलन करने के लिए सभी हितधारकों के साथ नियोजित है और सरकार के राहत उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करती है। सरकार एक व्यापक बहुआयामी कार्यनीति के माध्यम से भारतीय निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ उपायों के प्रभाव को कम करने के लिए लगातार कार्य कर रही है, जिसमें पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अमेरिकी सरकार के साथ गहन बातचीत, आरबीआई के व्यापार राहत उपायों के माध्यम से तत्काल राहत, निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के माध्यम से घरेलू मांग में वृद्धि, नए निर्यात संवर्धन मिशन जैसे निर्यात संवर्धन उपाय जो हमारे निर्यातकों को सहयोग और सहायता प्रदान करता है, नए देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता करना और मौजूदा मुक्त व्यापार समझौतों का बेहतर उपयोग करना शामिल है। यह उम्मीद की जाती है कि सामूहिक रूप से इन उपायों से भारत के समुद्री निर्यात में विविधीकरण और लचीलापन बढ़ेगा।

उपरोक्त उल्लिखित कुछ उपायों का विवरण निम्नवत है:

1. **निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम)**

यह मिशन वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक 25,060 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ निर्यात संवर्धन के लिए एक व्यापक, लचीला और डिजिटल रूप से संचालित फ्रेमवर्क प्रदान करेगा। ईपीएम कई विखंडित योजनाओं से एक एकल, परिणाम-आधारित और अनुकूलन तंत्र की ओर एक कार्यनीतिक बदलाव का प्रतीक है जो वैश्विक व्यापार चुनौतियों और निर्यातकों की उभरती ज़रूरतों का तेज़ी से प्रत्युत्तर कर सकता है।

यह मिशन दो एकीकृत उप-योजनाओं के माध्यम से परिचालित होगा:

(i) निर्यात प्रोत्साहन-ब्याज अनुदान, निर्यात फैक्टरिंग, संपार्श्विक गारंटी, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए क्रेडिट कार्ड और नए बाजारों में विविधीकरण के लिए ऋण वृद्धि संबंधी सहायता जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से एमएसएमई के लिए किफायती व्यापार वित्त तक पहुंच में सुधार लाने पर केंद्रित है।

(ii) निर्यात दिशा - गैर-वित्तीय सक्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करती है जो बाजार की तत्परता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाती है, जिसमें निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन संबंधी सहायता, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग के लिए सहायता, और व्यापार मेलों में भागीदारी, निर्यात भंडारण और लॉजिस्टिक, अंतर्देशीय परिवहन प्रतिपूर्ति तथा व्यापार आसूचना और क्षमता निर्माण पहल शामिल हैं।

यह मिशन भारतीय निर्यात को बाधित करने वाली संरचनात्मक चुनौतियों का सीधे तौर पर समाधान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- सीमित और महंगी व्यापार वित्त पहुंच,
- अंतर्राष्ट्रीय निर्यात मानकों के अनुपालन की उच्च लागत,
- अपर्याप्त निर्यात ब्रांडिंग और विखंडित बाजार पहुंच, और
- आंतरिक और कम निर्यात गहनता वाले क्षेत्रों में निर्यातकों के लिए लॉजिस्टिक संबंधी असुविधा

ईपीएम के तहत, हाल ही में वैश्विक टैरिफ वृद्धि से प्रभावित क्षेत्रों, जैसे वस्त्र, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और समुद्री उत्पादों को प्राथमिकता सहायता प्रदान की जाएगी। इन क्रियाकलापों से निर्यात ऑर्डरों को बनाए रखने, नौकरियों की सुरक्षित करने और नए भौगोलिक क्षेत्रों में विविधीकरण को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

2. निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना को भी मंजूरी दी गई है ताकि राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) को 100% ऋण गारंटी कवरेज प्रदान किया जा सके, ताकि एमएसएमई सहित पात्र निर्यातकों को 20,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त संपार्श्विक-मुक्त ऋण सुविधाएँ प्रदान की जा सकें। इस योजना से भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने और नए व उभरते बाजारों में विविधीकरण को बढ़ावा मिलने की प्रत्याक्षा है। संपार्श्विक-मुक्त ऋण पहुँच से लिक्विडी मजबूत होगी, सुचारू व्यावसायिक परिचालन सुनिश्चित होगा और 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति को मजबूती मिलेगी।

3. व्यापार राहत उपाय:-भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पात्र प्रभावित निर्यातकों के लिए व्यापार राहत उपाय भी शुरू किए हैं, जिसमें ऋण चुकौती स्थगन और निर्यात ऋण की अवधि बढ़ाने का प्रावधान शामिल है।

4. मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाना:- सरकार का लक्ष्य निर्यात विविधीकरण को बढ़ावा देना है और इसने अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ 15 मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और 6 अधिमान्य व्यापार समझौतों (पीटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार सभी हितधारकों के साथ मिलकर कार्य कर रही है ताकि हमारे निर्यातक जापान, कोरिया, यूएई आदि जैसे प्रमुख बाजारों के साथ भारत के एफटीए के लाभों का बेहतर उपयोग कर सकें और हाल ही में ईएफटीए देशों और यूके के साथ संपन्न एफटीए से उत्पन्न अवसरों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें। सरकार यूरोपीय संघ, पेरू, चिली, न्यूजीलैंड, ओमान आदि के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी एफटीए को शीघ्र संपन्न करने के लिए भी वार्ता कर रही है।

5. विविधीकरण उपाय:- निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप, यूरोपीय संघ और रूस को निर्यात के लिए सूचीबद्ध मत्स्य पालन प्रतिष्ठानों की संख्या में हाल ही में वृद्धि हुई है। मत्स्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से देश में मत्स्य पालन और जलीय कृषि के विकास के लिए कुल 21274.13 करोड़ रुपये के साथ परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। इससे इस क्षेत्र में भारत के निर्यात में दोगुने से अधिक की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2013-14 में 30,213 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 62,408 करोड़ रुपये हो गया है, जिसमें मूल्यवर्धित उत्पादों का हिस्सा 2% से बढ़कर 11% हो गया है।

सरकार अमेरिकी टैरिफ उपायों के उभरते प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए निर्यातकों, निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी), उद्योग संघों और राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के साथ नियोजित है।

*****